



करेंट अफेयर्स उत्तराखण्ड नवंबर 2024

(संग्रह)

अनुक्रम

उत्तराखंड	3
➤ दिवाली के प्रदूषण से बचने के लिये उत्तराखंड में शरण	3
➤ उत्तराखंड का दिवाली उपहार	4
➤ उत्तराखंड के गाँवों में HIV का प्रकोप	4
➤ उत्तराखंड जीवन-यापन सुधार परियोजना	5
➤ मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर	7
➤ चार धाम यात्रा 2024 के दौरान तीर्थयात्रियों की मृत्यु	8
➤ इगास बगवाल महोत्सव	9
➤ केदारनाथ के लैंडफिल में अनुपचारित अपशिष्ट	10
➤ उत्तराखंड की नदियों पर पर्यावरणीय संकट	11
➤ उत्तराखंड के चरागाह संरक्षण SOP	12
➤ राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना	13

उत्तराखंड

दिवाली के प्रदूषण से बचने के लिये उत्तराखंड में शरण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में NCR (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) क्षेत्र में वायु की निम्न गुणवत्ता ने निवासियों को स्वच्छ वायु और स्वस्थ दिवाली मनाने के लिये उत्तराखंड की ओर प्रेरित किया है।



प्रमुख बिंदु

- पर्यटक बुकिंग में बढ़ोतरी:
 - ◆ प्रदूषण से बचने के लिये NCR के निवासी उत्तराखंड में, विशेषकर देहरादून, नैनीताल और मसूरी जैसे क्षेत्रों में होटल और होमस्टे की बुकिंग तेजी से कर रहे हैं।
 - ◆ दिवाली के दौरान उत्तराखंड में प्रदूषण का स्तर अपेक्षाकृत कम रहता है, जिससे यह NCR के धुंध भरे आसमान के बीच एक आकर्षक शरणस्थल बन जाता है।
 - ◆ परिवार, विशेषकर बुजुर्ग और बच्चों वाले, शहरी क्षेत्रों में उच्च प्रदूषण स्तर से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों से बचने को प्राथमिकता देते हैं।
 - ◆ इस आगमन से उत्तराखंड की पर्यटन अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है, तथा आवास और स्थानीय सेवाओं की मांग बढ़ जाती है।

उत्तराखंड का दिवाली उपहार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड ने दिवाली लाभ के रूप में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये **महँगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA)** में वृद्धि की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- महँगाई भत्ते में बढ़ोतरी:
 - ◆ उत्तराखंड ने घरेलू खर्चों पर महँगाई के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से सरकारी कर्मचारियों के लिये महँगाई भत्ते में एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि की।
 - ◆ महँगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% प्रतिमाह कर दिया गया है।
 - ◆ महँगाई भत्ते में वृद्धि सभी नियमित और पूर्णकालिक राज्य कर्मचारियों एवं UGC से संबद्ध अधिकारियों पर 1 जुलाई 2024 से लागू होगी, जिसमें जुलाई से सितंबर 2024 तक का बकाया नकद देय होगा।
 - ◆ राज्य सरकार के अधीन कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कवर करते हुए बढ़ा हुआ महँगाई भत्ता तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
- आर्थिक प्रभाव:
 - ◆ यह वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ावा देती है, जो विशेष रूप से त्र्यौहारी सीजन के दौरान अधिक महत्वपूर्ण होती है, जब व्यय आमतौर पर अधिक होता है।
 - ◆ इसी प्रकार के महँगाई भत्ते के समायोजन विभिन्न राज्यों में देखे जा रहे हैं, क्योंकि इनका उद्देश्य बढ़ती जीवन-यापन लागत के बीच वित्तीय राहत प्रदान करना है।

महँगाई भत्ता (DA)

- यह महँगाई को संतुलित करने के लिये जीवन-यापन की लागत का समायोजन है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रदान किया जाता है। इसकी गणना मूल क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

उत्तराखंड के गाँवों में HIV का प्रकोप

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में नैनीताल के रामनगर में HIV प्रकोप की सूचना मिली है, जिससे नशीली दवाओं की लत और असुरक्षित यौन संबंधों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ी है।

प्रमुख बिंदु

- **HIV प्रसार:**
 - ◆ रामनगर में 19 से अधिक पुरुष असुरक्षित यौन संबंध के बाद **HIV** पॉजिटिव पाए गए।
 - ◆ अधिकारी इसे सामुदायिक स्वास्थ्य सतर्कता को और अधिक सख्त बनाने के लिये एक चेतावनी के रूप में बता रहे हैं।
- **भारत में HIV - आँकड़े:**
 - ◆ वर्ष 2022 तक, लगभग 2.47 मिलियन भारतीय **HIV** के साथ जी रहे हैं, तथा वयस्कों में इसकी व्यापकता दर 0.2% है।
 - ◆ वर्ष 2010 के बाद से नये संक्रमणों में 42% से अधिक की गिरावट आई है, तथा AIDS से संबंधित मौतों में लगभग 77% की कमी आई है।
- **सरकारी प्रयास:**
 - ◆ भारत का **राष्ट्रीय AIDS और STI नियंत्रण कार्यक्रम (2021-2025)** मुख्यतः घरेलू स्तर पर वित्त पोषित है, जिसका ध्यान रोकथाम, परीक्षण और उपचार पर केंद्रित है।
 - ◆ **सामाजिक न्याय मंत्रालय** नशे और मादक पदार्थों से संबंधित समस्याओं से ग्रस्त लोगों की सहायता के लिये एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन संचालित करता है।

ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस (HIV)

- **परिचय:**
 - ◆ HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशियेंसी वायरस, जो एक ऐसा वायरस है जो मानव शरीर की **प्रतिरक्षा प्रणाली** पर हमला करता है।
 - ◆ यह मुख्य रूप से CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं को लक्ष्य बनाता है और उन्हें क्षतिग्रस्त करता है, जो संक्रमणों और रोगों से लड़ने की शरीर की क्षमता के लिये आवश्यक हैं।
 - ◆ समय के साथ, HIV प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर अवसरवादी संक्रमणों (Opportunistic Infections) और **कैंसर** के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
- **संचरण:**
 - ◆ HIV मुख्यतः रक्त, वीर्य, योनि द्रव्य और स्तनपान जैसे कुछ शारीरिक तरल पदार्थों के आदान-प्रदान के माध्यम से फैलता है।
- **गंभीरता:**
 - ◆ यदि उपचार न किया जाए तो वायरस व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को नष्ट कर देता है और उन्हें **एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशियेंसी सिंड्रोम (AIDS)** चरण में कहा जाता है, जहाँ उसे कई अवसरवादी संक्रमण (Opportunistic Infections) होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हो सकती है।
- **उपचार:**
 - ◆ यद्यपि वर्तमान में इस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, फिर भी **एंटीरेट्रोवाइरल थेरेपी** का उपयोग करके इस रोग का प्रबंधन किया जा सकता है।
 - ◆ ये दवाएँ शरीर के भीतर वायरस की प्रतिकृति को नष्ट देती हैं, जिससे CD4 प्रतिरक्षा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है।

उत्तराखंड जीवन-यापन सुधार परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार और **एशियाई विकास बैंक (ADB)** ने उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी गतिशीलता सहित शहरी सेवाओं को बढ़ाने के लिये 200 मिलियन अमरीकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किये।

- शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास में और अधिक सहायता देने के लिये यूरोपीय निवेश बैंक 191 मिलियन अमेरिकी डॉलर के समानांतर निवेश के साथ इस परियोजना का सह-वित्तपोषण कर रहा है।

मुख्य बिंदु

- परियोजना के उद्देश्य:
 - ◆ यह परियोजना भारत के शहरी विकास एजेंडे और शहरी सेवाओं में सुधार के उत्तराखंड के लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शहरों में बेहतर जीवन-यापन और स्थायित्व सुनिश्चित करना है।
 - ◆ यह उत्तराखंड की आबादी को बाढ़ और भूस्खलन जैसे खतरों से बचाने के लिये जलवायु और आपदा-रोधी शहरी बुनियादी ढाँचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- परियोजना के अंतर्गत शामिल पहल:
 - ◆ उत्तराखंड के आर्थिक केंद्र हल्द्वानी में प्रमुख उन्नयन:
 - हल्द्वानी में जलवायु-अनुकूल सड़कें विकसित की जाएंगी, साथ ही कुशल यातायात प्रबंधन प्रणाली, CNG बसें और इलेक्ट्रिक बस पायलट भी विकसित किये जाएंगे।
 - इस परियोजना में वर्षा जल निकासी और सड़क किनारे नालियों का निर्माण तथा बाढ़ से निपटने के लिये पूर्व चेतावनी प्रणाली का क्रियान्वयन शामिल है।
 - हरित-प्रमाणित प्रशासनिक परिसर और बस टर्मिनल से सार्वजनिक सेवा वितरण में वृद्धि होगी।
- चार शहरों में जलापूर्ति और स्वच्छता में सुधार:
 - ◆ चंपावत, किच्छा, कोटद्वार और विकासनगर में परियोजना का लक्ष्य 100% जल सेवा कवरेज, जलवायु-अनुकूल पाइपलाइनें, ट्यूबवेल, नए जलाशय और जल उपचार संयंत्र स्थापित करना है।
 - ◆ सीवेज उपचार सुविधाओं के माध्यम से स्वच्छता कवरेज को बढ़ाया जाएगा।
 - ◆ महिला सशक्तीकरण एवं आजीविका के अवसर:
 - इस परियोजना के तहत महिलाओं को बस चलाने, टिकट बुक करने और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों के प्रबंधन जैसे कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाएंगे।
 - यह परियोजना कमजोर परिवारों की महिलाओं सहित महिलाओं को जल एवं स्वच्छता सेवाओं के संचालन एवं प्रबंधन में प्रशिक्षित करेगी।

एशियाई विकास बैंक (ADB)

- ADB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष 1966 में एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।
- इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और इसके 69 सदस्य हैं।
- यह एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होता है और सदस्यों के योगदान, ऋण से अर्जित आय तथा ऋण पुनर्भुगतान के माध्यम से वित्त पोषित होता है।

यूरोपीय निवेश बैंक (EIB)

- इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी और यह यूरोपीय संघ की ऋणदाता शाखा है।
- यह विश्व की सबसे बड़ी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं में से एक है तथा जलवायु वित्त का सबसे बड़ा प्रदाता है।
- वर्ष 1993 से, EIB धारणीय शहरी परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करके भारत की उभरती हरित महत्वाकांक्षाओं का समर्थन कर रहा है।

मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT)** ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-रुड़की (**IIT-रुड़की**) के साथ "5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिये मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर" के विकास के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- **मिलीमीटर वेव बैकहॉल प्रौद्योगिकी परियोजना:**
 - ◆ इसका उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर 5G कनेक्टिविटी के लिये मिलीमीटर वेव बैकहॉल प्रौद्योगिकी विकसित करना है।
 - सीमित संख्या में छोटे सेल-आधारित स्टेशनों (SBS) को फाइबर के माध्यम से नेटवर्क गेटवे से जोड़ा जाएगा, जिससे बुनियादी ढाँचे की जरूरतें कम हो जाएंगी।
 - ◆ ट्रांसीवर के विकास में संयुक्त ऑप्टिकल और मिलीमीटर तरंग दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा।
 - इससे प्रौद्योगिकी के समग्र आकार और लागत में कमी आने की उम्मीद है, जिससे यह अधिक कुशल और सस्ती हो जाएगी।
 - ◆ इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय **सेमीकंडक्टर** निर्माण उद्योगों पर भारत की निर्भरता को कम करना तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है।
 - ◆ यह **बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)** सृजित करने और मिलीमीटर वेव तथा SUB-THz प्रौद्योगिकी में कुशल कार्यबल विकसित करने तथा 5G और 6G में प्रगति के लिये तैयारी करने में योगदान देगा।
- **स्थानीय उद्योग और रोज़गार के लिये समर्थन:**
 - ◆ यह परियोजना लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों को भारत में विशेष रूप से बहुलक-आधारित और धातु-एकीकृत संरचनाओं में विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करती है।
 - ◆ स्थानीय विनिर्माण में वृद्धि से भारतीय इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।
- **TTDF योजना के अंतर्गत वित्तपोषण सहायता:**
 - ◆ यह समझौता दूरसंचार विभाग की **दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि (TTDF) योजना** के तहत हस्ताक्षरित किया गया है।
 - ◆ TTDF का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप्स, शिक्षाविदों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को वित्तपोषित करना तथा दूरसंचार उत्पादों और समाधानों के घरेलू विकास और व्यावसायीकरण में सहायता करना है।

मिलीमीटर तरंग

- **परिचय:**
 - ◆ यह एक क्वायरेस संचार तकनीक है जो डेटा संचारित करने के लिये उच्च आवृत्ति रेडियो तरंगों का उपयोग करती है।
 - ◆ मिलीमीटर तरंगों की आवृत्ति रेंज 30-300 GHz और तरंगदैर्घ्य रेंज 1-10 मिलीमीटर होती है।
- **उपयोग:**
 - ◆ 5G: 5G में मिलीमीटर तरंगों का उपयोग उच्च गति, बढ़ी हुई बैंडविड्थ संचार प्रदान करने के लिये किया जाता है।
 - ◆ विस्फोटक का पता लगाना: मिलीमीटर तरंगों कपड़ों के माध्यम से गुजर सकती हैं और शरीर से परावर्तित हो सकती हैं, जिससे इमेजिंग सिस्टम को छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में मदद मिलती है।
 - ◆ अन्य अनुप्रयोग: मिलीमीटर तरंगों का उपयोग व्यावसायिक और आवासीय ब्रॉडबैंड एक्सेस, कैंपस क्षेत्र नेटवर्क, आउटडोर वाई-फाई हॉटस्पॉट आदि के लिये किया जा सकता है।

टेलीमैटिक्स विकास केंद्र (C-DOT)

- इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। यह दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय का एक स्वायत्त दूरसंचार R&D (अनुसंधान और विकास) केंद्र है।
- यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी है।
- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) के साथ पंजीकृत सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान संस्थान है।

चार धाम यात्रा 2024 के दौरान तीर्थयात्रियों की मृत्यु

चर्चा में क्यों ?

वर्ष 2024 में उत्तराखंड में 192 दिनों की चार धाम यात्रा, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे ऊँचे स्थान वाले मंदिर शामिल हैं, में स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण 246 तीर्थयात्रियों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई।

प्रमुख बिंदु

- उत्तराखंड सरकार के आँकड़ों के अनुसार, चार धाम यात्रा में 47,03,905 से अधिक तीर्थयात्रियों ने भाग लिया, जो 10 मई 2024 को शुरू हुई और 17 नवंबर 2024 को समाप्त होने वाली है।
- ◆ वर्ष 2023 में मृत्यु दर 230 से अधिक हो गई, जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या 300 से अधिक थी।
- हेलीकॉप्टर यात्रा और स्वास्थ्य ज़ोरिखम:
 - ◆ केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने के लिये हेलीकॉप्टर का उपयोग करने वाले तीर्थयात्रियों में मृत्यु दर बहुत अधिक देखी गई। अनुकूलन के बिना उच्च ऊँचाई (लगभग 3,000 मीटर) पर तेज़ी से चढ़ने से स्वास्थ्य ज़ोरिखम बढ़ जाता है।
 - ◆ सभी चार धाम तीर्थस्थलों पर ऑक्सीजन की कमी से ऊँचाई संबंधी बीमारी हो सकती है, जो कि यदि तुरंत प्रबंधित न की जाए तो घातक हो सकती है।
 - ◆ अपर्याप्त आवास, मार्ग पर भीड़भाड़, चरम और परिवर्तनशील मौसम की स्थिति, तथा अपर्याप्त स्वास्थ्य जाँच जैसे मुद्दे।
- चार धाम यात्रा का आर्थिक प्रभाव:
 - ◆ इस यात्रा से प्रतिवर्ष लगभग 7,500 करोड़ रुपए की आय होती है, जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
 - ◆ यह यात्रा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करती है, जिसमें होटल कर्मचारी, गाइड, टैक्सी चालक, पुजारी, खच्चर संचालक, कुली और पर्यटन और हस्तशिल्प क्षेत्र के अन्य लोग शामिल हैं।
- आलोचना और चिंताएँ:
 - ◆ यद्यपि राज्य ने इस वर्ष तीर्थयात्रियों के लिये स्वास्थ्य जाँच अनिवार्य कर दी है, फिर भी उच्च मृत्यु दर ने चिंता उत्पन्न कर दी है।
 - ◆ नीति आयोग जैसे थिंक टैंक ने बार-बार भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत पर्यटन प्रथाओं का आह्वान किया है तथा राज्य से इन मानकों के अनुरूप कार्य करने का आग्रह किया है।

चार धाम यात्रा

- यमुनोत्री धाम:
 - ◆ अवस्थिति: उत्तरकाशी ज़िला।
 - ◆ समर्पित: देवी यमुना को।
 - ◆ यमुना नदी भारत में गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे पवित्र नदी है।

- गंगोत्री धाम:
 - ◆ अवस्थिति: उत्तरकाशी जिला।
 - ◆ समर्पित: देवी गंगा को।
 - ◆ सभी भारतीय नदियों में सबसे पवित्र मानी जाती है।
- केदारनाथ धाम:
 - ◆ अवस्थिति: रुद्रप्रयाग जिला।
 - ◆ समर्पित: भगवान शिव को।
 - ◆ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है।
 - ◆ भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों (भगवान शिव के दिव्य प्रतिनिधित्व) में से एक।
- बद्रीनाथ धाम:
 - ◆ अवस्थिति: चमोली जिला।
 - ◆ पवित्र बद्रीनारायण मंदिर का स्थान।
 - ◆ समर्पित: भगवान विष्णु को।
 - ◆ वैष्णवों के लिये पवित्र तीर्थस्थलों में से एक।

इगास बगवाल महोत्सव

चर्चा में क्यों ?

इगास बगवाल, जिसे बूढ़ी दिवाली या हरबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, दिवाली के 11 दिन बाद उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है। यह त्यौहार राज्य की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जो साझा परंपराओं और उत्सवों के माध्यम से समुदायों को एकजुट करता है।

प्रमुख बिंदु

- उत्पत्ति और महत्त्व:
 - ◆ इगास बगवाल कार्तिक शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है और यह भगवान विष्णु के चार महीने के विश्राम काल के अंत का प्रतीक है, जो नई शुरुआत के लिये एक शुभ समय है।
 - ◆ "इगास" शब्द उत्तराखंड में सांस्कृतिक गौरव और पौराणिक श्रद्धा से जुड़ा है।
 - ◆ ऐसा माना जाता है कि जब भगवान राम के अयोध्या लौटने की सूचना दिवाली के 11 दिन बाद उत्तराखंड पहुँची, तो स्थानीय लोगों ने अपने तरीके से दिवाली मनाई।
 - ◆ एक अन्य किंवदंती गढ़वाली योद्धा माधव सिंह भंडारी की दापाघाटी में तिब्बत पर विजय का जश्न मनाती है, जिसे समुदाय द्वारा एकता और वीरता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।
- भैलो- मशाल परंपरा:
 - ◆ ग्रामीण लोग देवदार की लकड़ियों को बांधकर भैलो या अंधाया नामक बड़ी मशालें बनाते हैं, जिन्हें जलाकर ऊपर की ओर घुमाया जाता है, जो अंधकार के निष्कासन का प्रतीक है।
 - ◆ ऐसा माना जाता है कि इस मशाल अनुष्ठान से देवी लक्ष्मी से समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है।
- त्यौहार अनुष्ठान और पशु सम्मान:
 - ◆ उत्तराखंड की कृषि जीवन शैली के लिये आवश्यक मवेशियों को इगास बगवाल के दौरान सम्मानित किया जाता है। ग्रामीण उन्हें नहलाते हैं और हल्दी और सरसों के तेल से सजाते हैं।

- ◆ पशुओं के लिये विशेष भोजन तैयार किया जाता है, तथा सांप्रदायिक सद्भाव का जश्न मनाने के लिये ग्रामीणों के बीच पारंपरिक व्यंजन बाँटे जाते हैं।
- **इगास बगवाल के संरक्षण के प्रयास:**
 - ◆ स्थानीय प्राधिकारी और सांस्कृतिक संगठन कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों के माध्यम से इगास बगवाल को बढ़ावा देते हैं, जिसका उद्देश्य त्योहार की विरासत को संरक्षित करना है।
 - ◆ युवा-केंद्रित पहल इगास बगवाल के सांस्कृतिक महत्त्व पर जोर देती है, तथा यह सुनिश्चित करती है कि इसकी विरासत भविष्य की पीढ़ियों तक बनी रहे।

केदारनाथ के लैंडफिल में अनुपचारित अपशिष्ट

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरणविद इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि अधिकारी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हिमालयी मंदिर केदारनाथ के आसपास लैंडफिल स्थलों पर टनों अनुपचारित अपशिष्ट डालना जारी रखे हुए हैं।

मुख्य बिंदु

- **केदारनाथ में अपशिष्ट डंपिंग:**
 - ◆ यह पता चला कि वर्ष 2022 और 2024 के बीच केदारनाथ के पास दो लैंडफिल साइटों पर 49.18 टन असंसाधित अपशिष्ट फेंका गया।
 - ◆ अनुपचारित अपशिष्ट उत्पादन में वृद्धि का रुझान देखा गया है, जो 2022 में 13.2 टन, 2023 में 18.48 टन तथा 2024 में अब तक 17.5 टन है।
- **पर्यावरणीय चिंता:**
 - ◆ कार्यकर्ताओं ने **अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली** की आलोचना की तथा इस बात पर जोर दिया कि **पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील केदारनाथ क्षेत्र** में उचित अपशिष्ट उपचार सुविधाओं का अभाव है।
 - **ग्लेशियरों** के बीच 12,000 फीट की ऊँचाई पर स्थित इस मंदिर के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिये तत्काल अपशिष्ट प्रबंधन सुधार की आवश्यकता है।
 - ◆ केदारनाथ के निकट दो लैंडफिल स्थल क्षमता के करीब पहुँच चुके हैं और निरंतर लापरवाही से इस क्षेत्र में वर्ष 2013 की आपदा जैसी एक और त्रासदी हो सकती है।
- **सरकारी एवं कानूनी निगरानी:**
 - ◆ **राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)** और **राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG)** ने शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को केदारनाथ में सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया।
 - NMCG ने पाया कि केदारनाथ से आने वाला अनुपचारित अपशिष्ट गंगा की सहायक नदी **मंदाकिनी** को प्रदूषित कर रहा है तथा **रुद्रप्रयाग** जिला प्रशासन को कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र

- पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र या पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र हैं।
- ईएसजेड को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

- ◆ संवेदनशील गलियारों, संपर्कता और पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण पैचों या रास्तों वाले स्थानों के मामले में, जो भूदृश्य संपर्कता के लिए महत्वपूर्ण हैं, यहाँ तक कि 10 किलोमीटर चौड़ाई से अधिक के क्षेत्रों को भी पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है।
- इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों में स्थित संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

उत्तराखंड की नदियों पर पर्यावरणीय संकट

चर्चा में क्यों ?

अपनी प्राचीन नदियों और झरनों के लिये जाना जाने वाला उत्तराखंड अभूतपूर्व पर्यावरणीय संकट का सामना कर रहा है।

- बदलते मौसम प्रारूप, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण राज्य की 206 बारहमासी नदियाँ और जलधाराएँ सूखने के कगार पर हैं।

मुख्य बिंदु

- **वर्तमान स्थिति:**
 - ◆ **सिंग एंड रिजुवनेशन अथॉरिटी (SARA)** की एक रिपोर्ट के अनुसार , उत्तराखंड में वर्तमान में 5,428 जल स्रोत खतरे में हैं।
 - ◆ SARA के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन जल निकायों के क्षरण के लिये प्राकृतिक कारणों के बजाय मानवीय हस्तक्षेप मुख्य रूप से जिम्मेदार है ।
- **SARA की स्थापना:**
 - ◆ इस संकट के जवाब में, उत्तराखंड सरकार ने अपनी बारहमासी नदियों और जलधाराओं की स्थिति की जाँच के लिये SARA की स्थापना की।
 - ◆ इस पहल का उद्देश्य इन महत्वपूर्ण जल स्रोतों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझना है।
 - ◆ SARA ने सभी संबंधित राज्य विभागों को एकजुट होकर इन जल निकायों की स्थिति पर डेटा प्रदान करने की अनुशंसा की है। इन निष्कर्षों ने सरकार के भीतर गंभीर चिंताओं को उत्पन्न किया है, जिसके परिणामस्वरूप तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
- **नदी पुनरुद्धार के लिये पायलट परियोजनाएं:**
 - ◆ SARA ने पाँच प्रमुख नदियों को पुनर्जीवित करने के लिये एक पायलट परियोजना तैयार की है:
 - देहरादून में सोंग नदी, पौड़ी में पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, नैनीताल में शिप्रा नदी और चंपावत में गौड़ी नदी।
 - राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH) और IIT रुड़की को इन नदियों का अध्ययन करने का कार्य निर्दिष्ट किया गया है तथा निष्कर्षों के आधार पर इस परियोजना को अन्य नदियों तक विस्तारित करने की योजना है।
- **जलवायु परिवर्तन का प्रभाव:**
 - ◆ जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि पिछले 150 वर्षों में विश्व के बाकी हिस्सों की तुलना में तिब्बत और हिमालय में अधिक स्पष्ट रही है।
 - ◆ इस खतरनाक प्रवृत्ति के कारण महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिणाम सामने आ रहे हैं, जिनमें जल स्रोतों का सूखना भी शामिल है।
 - ◆ जल संसाधन विभाग के आँकड़ों द्वारा स्पष्ट होता है कि राज्य में 288 जल स्रोतों में मूल जल स्तर का 50% से भी कम जल बचा है तथा लगभग 50 स्रोतों में 75% से भी कम जल बचा है।

- संबंधित अवलोकन और प्रभाव:

- ◆ पर्यावरणविदों और स्थानीय अधिकारियों ने जल स्तर और नदी के मार्ग में भारी परिवर्तन देखा है।
- ◆ भीमताल में झील मैदान जैसी दिखने लगी है तथा अन्य नदियों और जल स्रोतों में भी इसी प्रकार का संकट उभर रहा है।
- ◆ जलवायु वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के कारण पहाड़ टूट रहे हैं और नदियाँ या तो अपना मार्ग बदल रही हैं या **बाढ़** के दौरान तबाही मचा रही हैं।
- ◆ हल्द्वानी में गौला और कोसी नदियों का जलस्तर गिर गया है, जिससे पेयजल और सिंचाई का संकट उत्पन्न हो गया है।



उत्तराखंड के चरागाह संरक्षण SOP

चर्चा में क्यों ?

उत्तराखंड सरकार का वन विभाग राज्य के ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में घास के मैदानों के संरक्षण हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करेगा।

- इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों के कारण होने वाले **भूस्खलन** और भूमि अवतलन की बढ़ती आवृत्ति को रोकना है।

मुख्य बिंदु

- चरागाह संरक्षण पहल:

- ◆ संवेदनशील पारिस्थितिकी क्षेत्र दयारा बुग्याल ने पिछले पारिस्थितिकी बहाली प्रयासों से सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। इन लाभों को अन्य घास के मैदानों तक पहुँचाने के लिये, वन विभाग संरक्षण के लिये एक SOP विकसित करने की योजना बना रहा है।
 - यह SOP जैविक दबाव को कम करने तथा आगे क्षरण को रोकने पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- ◆ बुग्याल संरक्षण योजना के तहत अब तक 22 घास के मैदानों की लगभग 83 हेक्टेयर भूमि पर संरक्षण कार्य किया जा चुका है।

● हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र:

- ◆ अपने दौरे के दौरान अधिकारियों ने गंगोत्री के निकट लंका में निर्माणाधीन **हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र** का भी निरीक्षण किया।
 - आशा है कि यह केंद्र एक वर्ष के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे पर्यटकों को प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करने तथा हिम तेंदुओं को उनके प्राकृतिक आवास में देखने का अवसर मिलेगा।
- ◆ **गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान** पिछले दशक में एक महत्वपूर्ण ट्रांस-हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उभरा है।
- ◆ भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पार्क में हिम तेंदुओं की पर्याप्त उपस्थिति दर्ज की है, जो हाल तक अपेक्षाकृत अज्ञात थी।

राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने विभिन्न राज्यों में **आपदा न्यूनीकरण** और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिये 1,115.67 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु

- **समिति:**
 - ◆ समिति ने **राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF)** के अंतर्गत 15 राज्यों में भूस्खलन जोखिम को निम्न करने के प्रस्तावों की समीक्षा की।
 - ◆ इसने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहल के लिये **राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF)** से वित्त पोषण को भी मंजूरी दी।
- **15 राज्यों के लिये 1,000 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना को मंजूरी दी गई।**
 - ◆ राज्यवार आवंटन:
 - उत्तराखंड: 139 करोड़ रुपए
 - हिमाचल प्रदेश: 139 करोड़ रुपए
 - आठ पूर्वोत्तर राज्य: 378 करोड़ रुपए
 - महाराष्ट्र: 100 करोड़ रुपए
 - कर्नाटक: 72 करोड़ रुपए
 - केरल: 72 करोड़ रुपए
 - तमिलनाडु: 50 करोड़ रुपए
 - पश्चिम बंगाल: 50 करोड़ रुपए
 - ◆ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये 115.67 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मंजूरी दी गई।
- **समिति द्वारा पूर्व अनुमोदन:**
 - ◆ **शहरी बाढ़ जोखिम शमन परियोजनाएँ:** सात शहरों के लिये 3,075.65 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ **शहरी बाढ़** जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
 - ◆ **GLOF (ग्लेशियल लेक आउटबस्टर्ट फ्लड) जोखिम प्रबंधन परियोजनाएँ:** NDMF के तहत 150 करोड़ रुपए की कुल लागत पर चार राज्यों के लिये **GLOF** को मंजूरी दी गई।

राष्ट्रीय आपदा राहत कोष

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधिनियमन के साथ राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (NCCF) का नाम बदलकर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) कर दिया गया।
- ◆ इसे आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46 में परिभाषित किया गया है।
- किसी भी आपदा की आशंका वाली स्थिति या आपदा के कारण आपातकालीन प्रतिक्रिया, राहत और पुनर्वास के लिये व्यय को पूरा करने के लिये इसका प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
- ◆ यह गंभीर प्रकृति की आपदा की स्थिति में SDRF की सहायता करता है, बशर्ते SDRF में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न हो।

ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़ (GLOF)

- हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) एक विनाशकारी बाढ़ की स्थिति है, जो तब उत्पन्न होती है जब हिमनद झील का बाँध टूट जाता है, जिसके परिणामस्वरूप विशाल मात्रा में जल का प्रवाह होता है।
- इस प्रकार की बाढ़ आमतौर पर ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने या भारी वर्षा या पिघले जल के प्रवाह के कारण झील में जल के जमाव के कारण होती है।
- ◆ फरवरी 2021 में उत्तराखंड के चमोली ज़िले में अचानक बाढ़ आई, जिसके बारे में संदेह है कि यह GLOF के कारण आई थी।

दृष्टि
The Vision